E-Mail

पुनरीक्षण–2018

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष– 2236685– फैक्स– 0771–2224476,2236684,

Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

क्र.–01/03/निर्वा.नामा./पुनरीक्षण/2017–18/1230 रायपुर, दिनांक 31/08/2017

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त (छ0ग0)

विषयः–फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2018–पुनरीक्षण कार्यक्रम बावत् ।

विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2018 के सन्दर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम पत्र कमांक–23/LET/FUNC/ERD-ER2017(Vol.II) पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2017 के माध्यम से जारी किया गया हैं।

2. **Pre-Revision Activities**-इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नॉकित कार्यवाही आपके जिले में सुनिश्चित करें–

1. सर्व संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
2. मृत मतदाता, डुप्लीकेट नामों को हटाने की कार्यवाही ।
3. मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण (मतदान केन्द्रों एवं अनुभागों के डिजिटल मैप तैयार करना)
4. घर–घर सत्यापन के दौरान शेष मतदाताओं के फोटो एकत्रित करना ।
5. कंट्रोल टेवल अपडेट करना ।
6. स्वीप (SVEEP)हेतु विस्तृत Action Plan तैयार करना ।
7. फार्मेट 1–8 तैयार करना ।
8. पूरक सूची–2 का मुद्रण ।

3. भारत निर्वाचन आयोग नई–दिल्ली के निर्देशानुसार भविष्य में सभी विधानसभा/लोकसभा निर्वाचनों में VVPAT का उपयोग किया जावेगा । ग्रामीण क्षेत्र में 1200 एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम् 1400 मतदाता होना चाहिये । सभी मतदान केन्द्रों के Latitude and Longitude की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय/भारत निर्वाचन आयोग नई–दिल्ली के वेबसाईट में अपडेट करना ।

4. **पुनरीक्षण कार्यक्रम** –अर्हता 01 जनवरी, 2018 की स्थिति में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है–

Schedule of Special Summary Revision 01-01-2018

स.क्र.	पुनरीक्षण कार्यक्रम	प्रत्येक चरण के निर्धारित अवधि
1	मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन	23 अक्टूबर, 2017 (सोमवार)
2	दावे/आपत्ति दर्ज करने की समयावधि	23 अक्टूबर, 2017 (सोमवार) से 22 नवम्बर, 2017 (बुधवार) तक
3	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं RWA (रेसीडेंस वेलफेयर सोसायटी) आदि की बैठकों में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन करना	29 अक्टूबर, 2017 (रविवार)
4	राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. के साथ दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान	05 नवम्बर, 2017 (रविवार)
5	दावा/आपत्तियों का निराकरण	12 दिसम्बर 2017 (मंगलवार) तक
6	डाटाबेस में अपडेशन, फोटो मार्जिंग, कन्ट्रोल टेबल का अपडेशन, एवं पूरक सूची की तैयारी व मुद्रण	30 दिसम्बर, 2017 (शनिवार) तक
7	मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन	10 जनवरी, 2018 (बुधवार)

5. **कार्यक्रम का प्रचार प्रसार–**

सभी राजनैतिक दलों तथा प्रेस–मीडिया को कार्यक्रम की समय सारणी से अवगत करावें । इसकी प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी करें । समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जावे ।

6. **राजनैतिक दलों की बैठक–**

प्रेस–मीडिया व राजनैतिक दलों की बैठक–सतत् अन्तराल पर राजनैतिक दलों की तहसील व जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करें तथा प्रेस–मीडिया के साथ भी मीटिंग (बैठक) करना सुनिश्चित करें ।

राजनैतिक दलों को बैठक में निम्न जानकारी दी जावे–

A निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2018 कार्यक्रम की जानकारी से अवगत कराया जावे ।

B विधिक प्रावधान तथा फार्म 6,6क,7,8, एवं 8क तथा नियमों की जानकारी दी जावे।

C आयोग के अद्यतन निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया जावे।

D बी.एल.ए नियुक्ति करने के संबंध में जानकारी–

- उन्हें यह भी बताया जावें कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 के दौरान दिनांक 05 नवम्बर, 2017 (रविवार) को विशेष अभियान चलाया जावेगा जिसमें बी.एल.ओ., मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बी.एल.ए के साथ मतदाता सूची की शुद्धता की पहचान करेंगे।
- एक बार बी.एल.ए. नियुक्त किये जाने पर वह व्यक्ति तब तक बी.एल.ए. बना रहेगा जब तक संबंधित राजनैतिक दल द्वारा नियुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें हटाया नहीं जाता ।
- राजनैतिक दलों की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबल अभिकर्ताओं को बड़ी संख्या में आवेदन जमा कराने की अनुमति दी है बशर्ते बूथ लेबल अभिकर्ता एक बार में अथवा एक दिन में बूथ लेबल अधिकारी को 10 से अधिक फार्म जमा नही करवायेगें । यदि बूथ लेबल अभिकर्ता दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूरी अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन/प्रपत्र जमा कराते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं ही सत्यापन किया जायेगा । फार्म के साथ बूथ लेबल एजेंट आवेदन प्रपत्रों की सूची तथा घोषण पत्र भी जमा करवायेगें कि उन्होंने आवेदन फार्म के ब्यौरों का निजी तौर पर सत्यापन कर लिया है और वे इसकी यथातथ्यता के संबंध में संतुष्ट है ।

E Toll free no. 1950 के संबंध में जानकारी दें ।

F मतदाता का नाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,छ0ग0रायपुर की वेबसाइट से ढूंढने की प्रकिया की जानकारी दी जावे ।

G राजनैतिक दलों को यह भी बताए कि पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावे/आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा उस पर आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस बावत् लिखित सूचना मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी जानी है तथा बैठक में भी अवगत कराया जाना है ।

H मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की मूल सूची की एक–एक प्रति व एक फोटोरहित मतदाता सूची के पीडीएफ की सीडी निःशुल्क प्रेस–मीडिया की उपस्थिति में उपलब्ध कराई जावे तथा उनकी पावती भी संधारित की जावे ।

7. **अधिकारी व कर्मचारियों की व्यवस्था–**

- बूथ लेवल अधिकारी, अविहित अधिकारियों एवं सुपरवाईजर की नियुक्ति समय पर पूर्ण कर लें । स्थानातंरण, सेवा निवृत्ति या पद रिक्त होने की स्थिति पर नये बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त कर लें ।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिये अधिसूचित पदों पर कार्यरत् अधिकारियों के नाम व मोबाईल नंबर की प्रविष्टि PGR में कर लेवें । ERO साफ्टवेयर एवं ERO NET के संचालन के लिये सही नाम व मोबाईल नंबर की प्रविष्टि अनिवार्य है । उप जिला निर्वाचन अधिकारियों व तकनीकी स्टॉफ का दायित्व होगा कि किसी भी अधिकारी का स्थानातंरण पदभार बदलने पर तत्काल आवश्यक सुधार UMS एवं PGR में करें तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को शीघ्र अवगत करावें ।
- PGR में BLOs के नाम की प्रविष्टि पूर्ण कर लें । आयोग को प्रस्तावित नये मतदान केन्द्रों के लिये BLOs, सुपरवाइजर का चिन्हॉकन कर लें तथा आयोग से मतदान केन्द्रों के अनुमोदन उपरांत उनकी भी प्रविष्टि तत्काल कर लें । प्रशिक्षण उपरांत BLOs, सुपरवाइजर की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों में संशोधन भी कर लें ।
- तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर का चयन कर लें ।
- डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था कर लें ।
- अविहित अधिकारी की नियुक्ति मतदान केन्द्रों की संख्या व मतदान केन्द्र लोकेशन के आधार पर कर लें ।

9. **कम्प्यूटर स्केनर एवं इंटरनेट की व्यवस्था–**

इस बार Ero Net पर काम किया जाना है । इसमें आवेदनों की प्रविष्टि करते समय इंटरनेट की आवश्यकता होगी इस हेतु जिले व तहसील स्तर में नेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे ।

9. **Observers-**

मतदाता सूची के लिए प्रेक्षक पूर्ववत संभागायुक्त रहेंगे। आयोग द्वारा अतिरिक्त प्रेक्षक आयोग के अधिकारियों या रोल आब्जर्बर को भी भेजा जायेगा । Roll Auditors भी रेंडम चेकिंग ,आडिट व पुनरीक्षण का पर्यवेक्षण करेंगें । अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची से संबंधित सभी रिकार्ड्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट रखें । साथ ही सभी Field गतिविधियों की सूची भी रखें ।

10. मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा फार्मेट 1–8 तैयार किया जावेगा । इसके लिये आयोग द्वारा दिये गये Component विधि का उपयोग कर अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2018 की स्थिति में जनसंख्या प्रोजेक्ट की जावेगी । इस संबंध में आपके जिले द्वारा कंट्रोल टेबल में 2011 की स्थिति में जनसंख्या की एंट्री की गई थी, जिसमें आवश्यक परिवर्तन कर लेवें एवं Component विधि का उपयोग कर विधानसभावार प्रोजेक्टेड जनंसख्या भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

11. दावा–आपत्तियों की सूची प्रदर्शनः–

A-आवेदनों की प्रविष्टिः–प्राप्त फार्म–6, 6ए,7,8एवं 8क की दिन–प्रतिदिन प्रविष्टि दावा आपत्ति पोर्टल की वेबसाईट पर की जानी है जिससे राजनैतिक दल एवं आम नागरिक आवेदनों पर होने वाली कार्यवाही से अवगत हो सकें और आपत्ति दाखिल कर सकें ।

B- ERO द्वारा प्राप्त दावा–आपत्तियों की सूची सभी राजनैतिक दलों को साप्ताहिक रूप से दी जावेगी तथा उसकी पावती प्राप्त की जावेगी। उन्हें यह भी बताया जावेगा कि सूची पर आपत्ति होने पर वह ERO के समक्ष आपत्ति कर सकते है । यह सूची संचयी न होकर बढ़ते हुए कम में होनी चाहिए ।

12. **दावा आपत्तियों पर निर्णय–** निम्नलिखित प्रक्रिया के उपरान्त दावा आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा :–

A-सभी दावें और आपत्तियों की सूची के प्रकाशन करने के कम से कम सात पूर्ण दिवसों की अवधि बीत चुकी होः–

- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए क्लिक करने वाली सूचियों के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के फार्म 9,10,11 तथा 11क में)
- मतदान केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के फार्म 9,10,11 तथा 11क में)
- मृत्यु वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में उस व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस दिया जाएगा जिसके नाम को हटाने पर विचार किया जा रहा है।

B. राजनैतिक दलों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों की सूची देने के पश्चात कम से कम सात पूर्ण दिवस बीत चुके हों ।
ऐसी सभी विलोपन जो कि मृत्यु के कारण दिए जाने है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की तथ्यों के आधार पर संतुष्टि के पश्चात ही किए जायेगें ।

13. **विलोपन के निर्णय के पूर्व सत्यापन–**

- मृत्यु के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में विलोपन प्रकरणों में तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी के द्वारा परीक्षण कराया जाना चाहिए, उसके बाद ही अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए ।
- किसी मतदान केन्द्र में जहां कुल मतदाता संख्या के 2 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता के नाम विलोपन होते है, वहां ERO स्तर से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा 5 प्रकरणों में आपत्ति कर नाम कटवाने की स्थिति पर भी परीक्षण किया जाना है।
- **विलोपन के पश्चात सत्यापन**–मृत्यु के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में नाम काटने की स्थिति मे ई.आर.ओ. द्वारा आदेश पारित करने के उपरान्त निम्नानुसार विधि में पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा प्रति सत्यापित किया जाना चाहिए :–

A- उप जिला निर्वाचन अधिकारी या समकक्ष अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत ।

B. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत ।

C. रोल आब्जर्बर द्वारा 0.5 प्रतिशत ।

14. **मतदाता सूची का एकीकरण**– मतदाता सूची के एकीकरण के पूर्व निम्न कार्य पूर्ण कर लें–

- NVSP या CGWS में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन या Manual प्राप्त आवेदनों का पूर्ण निराकरण कर लिया जावे । वर्तमान में जिलों में लंबित आवेदनों की जानकारी संलग्न कर प्रेषित है जिसमें कई आवेदन ERO के आदेश के लिये लंबित है तथा कई आवेदन अपलोड करने के लिये लंबित है ।
- आयोग के निर्देशानुसार चूंकि अब मतदाता सूची में गूगल मैप नक्शे प्रिंट किये जावेगें । सभी नक्शे युक्तियुक्तकरण के पश्चात् किंतु प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के कंट्रोल टेबल वेबसाइट में एवं ECI NET में अपलोड कर लेवें ।

15. Health Analysis of Electoral Roll –

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 के प्रारंभ में जिला, विधानसभा एवं मतदान केन्द्रवार लिंग अनुपात, EP रेसियो तथा 18–19 आयु वर्ग के पंजीयन के संबंध में विश्लेषण कर लेवें । इसमें विभिन्न श्रेणियों में विधानसभा व मतदान केन्द्रों को रखा गया था । इसके लिये मतदान केन्द्रवार, जनगणना, ग्रोथ रेट आदि की प्रविष्टि भी जिलों से करवाई गई थी ।

उक्त विश्लेषण के आधार पर Gap का कारण पता कर उन्हें दूर करने की कार्ययोजना बनाने तथा Gap दूर करने के निर्देश दिये गये थे । निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 के प्रारंभ में पुनः मतदाता सूची का Health Analysis किया जावे तथा जिले की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

16. **प्रारंभिक प्रकाशन की पूर्व अनुमति–**

मतदाता सूची के एकीकरण के बाद फार्मेट 1 से 8 में जानकारी तथा उसके विश्लेषण के साथ DEO को अपनी रिपोर्ट दिनांक **05 अक्टूबर, 2017** तक मुनिप कार्यालय को भेजनी है । प्रतिवेदन में जिन indicators में कमी है, उन्हें दूर करने के लिए Action plan भी बताया जाना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर **16 अक्टूबर, 2017** को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी जावेगी । उक्त प्रतिवेदन के पश्चात ही आयोग द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन की अनुमति दी जावेगी। कृपया अपने प्रतिवेदन (फार्मेट 1 से 8 सहित) कार्यालय में सुरक्षित भी रखें, जिसे मुनिप एवं रोल आब्जर्बर द्वारा भमण के दौरान भी देखा जा सके ।

17. **अंतिम प्रकाशन के पूर्व अनुमति (फार्मेट 1 से 8)–**

इसी प्रकार अंतिम प्रकाशन के पूर्व अनुमति के लिये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण व अपडेशन के पश्चात् पुनः फार्मेट 1 से 8 तैयार किया जाना है । इसका विश्लेषण कर फार्मेट 1 से 8 के साथ मुनिप कार्यालय को दिनांक **16/12/2017** तक प्रेषित किया जाना है । मुनिप कार्यालय द्वारा आयोग को उक्त प्रतिवेदन भेजकर अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त की जावेगी। आयोग द्वारा इस हेतु मुनिप कार्यालय को **20/12/2017** के पूर्व प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए है। कृपया इस समय–सीमा का ध्यान रखें । आयोग के अनुमोदन के बिना अंतिम प्रकाशन नहीं किया जा सकता है।

18. **मॉनिटरिंग**–निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2018 के लिये भारत निर्वाचन आयोग नई–दिल्ली द्वारा बनाये गये मॉनिटरिंग के CEO पोर्टल में DEO/ERO के लॉगइन से नियमित रूप से जानकारी अपडेट करना है ।

18. **बीएलओ वर्किंग कॉपी–**

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बूथ लेवल अधिकारियों को वर्किंग कॉपी दी जानी है । यह ध्यान रखें कि मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण तथा मतदाता सूची के एकीकरण के बाद मतदान केन्द्रों के क्रमांक व सीरियल नंबर बदल जाते है । अतः पुरानी वर्किंग कॉपी बूथ लेवल अधिकारी के पास रहने से उन्हें संदेह रहेगा । उचित होगा कि बूथ लेवल अधिकारी को नई वर्किंग कॉपी देने के पूर्व पुरानी सभी वर्किंग कॉपी जमा कर लेवें तथा उन्हें उचित रूप से संधारित रखें ।

19. **EPIC निर्माण–**

प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 25 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा । 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पहलीबार पंजीकृत होने वाले मतदाताओं को इस दिन औपचारिक रूप से मतदाता फोटो परिचय पत्र वितरित किया जाता है । कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये **दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक तैयार कर लिये जावे एवं** बूथ लेवल अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जावे ।

15. **प्रपत्रों की उपलब्धता–**

जिलों को प्रपत्र 6,7,8,8A, 9, 10,11 व 11A एवं अनुबंध–II,(शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप–18–21 वर्ष आयु समूह में पहली बार के आवेदक जिसके पास आयु का प्रमाण नही है, के माता/पिता/गुरू द्वारा लिया जाय/किया जाये) अनुबंध–III, (घोषणा–पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले 21 आयु समूह) अनुबंध–IV,(घोषणा–छात्रावासों/मेस/अन्यत्र रह रहे छात्रों द्वारा घोषणा) अनुबंध–V,(घोषणा–प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड–एपिक जारी करने के लिये) अनुबंध–I, (घोषणा–शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप) अनुबंध–II,(प्ररूप आईडी, ईसीआई–एपिक–001, प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी करने के लिये आवेदन, अनुबंध–I,(प्ररूप आईडी, ईसीआई–एपिक–001, प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी करने के लिये आवेदन,शपथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छ0ग0 रायपुर द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें । अपनी आवश्यकता अनुसार इसका आकंलन कर लिया जावे तथा मांग पत्र भी प्रेषित कर दिया जावे ।

16. **SVEEP ACTIVITY–**

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2018 के दौरान SVEEP गतिविधियां भी की जानी है । इसके लिये आपको पृथक से पत्र जारी किया जावेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों से राज्य के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रति प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

31/8/17

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़,रायपुर

पृ. क्र.–01/03/निर्वा.नामा./पुनरीक्षण/2017–18/1231 रायपुर, दिनांक 31-8-2017

प्रतिलिपि–

1. श्री एन.एन.बुटोलिया, प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संभागायुक्त, समस्त छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3. Ji CEO/Ji CEO(SVEEP)/Dy CEO/DDF/ACEO की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।
4. बजट शाखा मतदाता सूची के मुद्रण हेतु आवश्यक आबंटन उपलब्ध कराने एवं स्टोर शाखा की ओर पुनरीक्षण में आवश्यक प्रपत्रों की व्यवस्था हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़,रायपुर

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

By Email/Speed Post

No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER2017 (Vol.II)

Dated: 23rd August, 2017

To

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories,
(Except Gujarat and Himachal Pradesh).

Subject: - Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2018 as qualifying date - Programme - regarding.

Sir,

I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1st January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year) so that final publication of the electoral rolls could be made in the first week of January of the succeeding year. The revision schedule is prepared in such a manner that the electoral rolls are finally published much before National Voters' Day (25th January of every year) so that EPICs generated for new electors especially young voters (18-19 years) can be distributed to them in ceremonial manner on the day of NVD .

2. As the revision of electoral rolls actually starts with draft publication of electoral rolls, various pre-revision activities are required to be completed well before the actual commencement of Revision of Electoral Rolls with draft publication of electoral roll with the sole intention of achieving high fidelity electoral rolls. Accordingly, pre-revision activities like Training and Orientation of EROs/AEROs, Appointment of Booth Level Officers (BLOs) and their Training and Orientation, Identifications of critical gaps/deviations in electoral rolls and strategy to bridge/remove the same, deletion of identified multiple entries/dead electors entries after service of due notice, De-duplication campaign to remove duplicate entries in the electoral roll, Rationalization/modification of Polling Stations (including standardization and mapping of polling stations, determination of parts/section boundaries, optimization of sections and preparation of improved digital maps of polling areas), Photography campaign for residual electors whose images are not available in the roll (H2H campaign to collect images of residual electors), Preparation of CEO's website for draft publication of integrated rolls and providing search facility, Standardization of search facility at website, updating of Control Tables (including polling stations updating) and database and integration of rolls (irrespective of whether it is election or non-election year), preparation of detailed action plan for SVEEP etc. have been planned by the States/UTs in pursuance of the Commission's letter No.

Tel : 011-23052205-18 Fax: 011-23052223-25, Website : www.eci.nic.in
''मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी''
Greater participation for a stronger democracy

23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (VOL.II), dated 2nd August 2017 and the schedule, for pre-revision activities, fixed so, has to be strictly followed for its successful completion before draft publication of electoral rolls . A detailed report on completion of pre-revision activities shall be sent by the Chief Electoral Officer to the Secretary in charge of the respective State in the Commission.

3. As the Commission has decided to use VVPAT in all the future elections, no relaxation /deviation will be allowed in the upper limit of 1200 and 1400 electors in rural and urban polling stations respectively. The Commission has, therefore, directed all the polling stations with electors beyond the said upper limit will be invariably rationalized/modified as a pre-revision activity. For the rationalization/modification of Polling Station, rationalization of the part boundaries will be done as per the Commission's direction on upper ceiling of number of electors in urban and rural area and creation of new Polling Station shall be resorted to only after rationalizing the sections to adjacent Polling Station. Proposal on change of location shall be sent to the Commission only after physical verification/inspection of all the Polling Stations and along with its Longitude and latitude. Latitude and Longitude of all Polling Stations, newly identified and proposed for creation/change of location of Polling Stations shall be captured and details of the same shall be updated in the Dashboard.

4. The Commission has decided to take up revision of electoral rolls with reference to 1st January 2018 as the qualifying date. The revision shall be a Special Summary Revision in all States and Union Territories (except Gujarat and Himachal Pradesh) and shall be undertaken as per the schedule annexed to this letter, in accordance with Manual on Electoral Roll, 2016 along with subsequent instructions with regards to revision of electoral rolls /registration of electors, issued from time to time by the Commission. No change in the dates in the schedule approved by the Commission will be permitted.

5. Adequate publicity and awareness drive shall be ensured by DEOs and CEO regarding the summary revision programme. All the DEOs and CEO shall get the revision schedule properly disseminated to media, political parties and social organizations/RWAs and reach out to electors/eligible population extensively well before the date of draft publication of electoral rolls. For making the purpose of publication of draft rolls effective, series of SVEEP events, multiple and periodic meetings with political parties at Taluk, district and state levels and regular press meets may be organized. All DEOs and CEO shall separately call meetings of political parties and explain the schedule and seek cooperation expected of them before the date of draft publication. The draft publication should be done on the approved date with due fanfare publicity and the copies of draft rolls should be handed over to recognized political parties in public meeting in the presence of press and media. In any case, proper acknowledgement receipts from the representatives of political parties must be obtained and kept in record.

6. The CEO should write to all recognized national and state level political parties informing them the important points of the law and procedures of the revision and seek their cooperation in the roll revision exercise. A copy of letter issued to them may be endorsed to the Commission for record.

7. CEO will request to the recognized political parties to identify and appoint Booth Level Agent (BLA) for each polling station who would be associated with the Special Campaign for Roll Revision process on special campaign dates along with BLO. On these Special Campaign dates, the BLOs will go through the draft electoral roll with BLAs of recognized political parties of State concerned and identify the corrections, etc. It is pertinent to mention that BLAs once appointed from a recognized political party will continue as BLA, unless their appointment is rescinded /revoked by the political party concerned.

8. In addition to Divisional Commissioners, who shall act as Electoral Roll Observers for districts comprised within their Divisions, the Commission may depute its observers/ECI officers/roll auditors to randomly check, audit and supervise the revision process. Hence, it is absolutely essential that all roll related records including reports of progress as well as lists of the locations where field operations are in progress, should be kept up to date and made available to the observers.

9. The electors' information in prescribed Formats 1-8 related to draft publication of the electoral roll shall be furnished by the CEO along with his studied comments and explanatory memoranda to the Commission well before draft publication. Every DEO/ERO will do the similar study for his/her District/Assembly Constituency and forward the same to the CEO and also keep this ready for reference by Roll Observer/CEO. CEOs shall adopt the same methodology for estimation of projected 18+ population (age cohort wise) on 01.01.2018 as prescribed by the Commission during the recently concluded Special Drive, 2017. The State/UT, who is at variance with the methodology, as suggested by the Commission, may use their own methodology, if they feel that it is more scientific and realistic in context of the concerned State and in such case CEO has to mention about the rationale behind keeping existing methodology in the Format 1-8.

10. The CEO shall take prior written clearance of the Commission for final publication of the electoral rolls. A request to that effect shall be made to the Commission by the Chief Electoral Officer along with Formats 1-8 by **20th December, 2017** and with Formats 1-8, memoranda/note mandatorily on how the roll revision process has achieved the targets fixed and the strategy to address any shortfalls during continuous updating may also be furnished. This should, in any case, be done at least 7 days before the date of final publication, so that clearance of the Commission may be conveyed at least 3 days before the date of final publication.

11. It may further be noted that all communications and clarification relating to the revision should be addressed to the Pr. Secretary/Secretary (in charge of the State/UT) in the Commission who will not only

reply to the CEO concerned without any delay but also ensure that there is no slippage in the roll revision programme of the States under their charge. They will closely monitor the pre-revision activities and roll revision programme of their respective States/UTs therefore, the CEOs must forward requisite report on progress of revision process at regular interval.

12. In order to facilitate the stakeholders and bringing more transparency in the process of electoral registration, the practice of computerization and posting of all application forms received in Forms 6, 6A, 7, 8 and 8A on the website of the CEO on a day to day basis, shall continue. The status of each application form should be clearly visible on each row of the list. Further, the web application used for this purpose should also provide a facility, that on clicking on any row in the list, the concerned application form can be printed by any citizen.

13. DEOs/EROs shall do Periodic reporting of progress made during the revision process regularly by making entries in prescribed Formats available at ECI dashboard, in accordance with the procedure laid down therein. The CEO shall check it to ensure its up to date status. It is reiterated for absolute compliance by all the concerned that dash board has to be kept updated at all times. Any lapse on part of the concerned officer shall expose him /her to disciplinary actions.

14. With a view to ensure more involvement of political parties, the Commission has allowed BLAs of a recognized political parties to file applications in bulk, subject to the condition that a BLA shall not submit more than 10 Forms to BLO at one time/in one day. If a BLA files more than 30 Applications/Forms during entire period of filing claims and objections, then the cross verification must be done by ERO/AERO themselves. Further, the BLA will also submit a list of application forms with a declaration that he has personally verified the particulars of the application forms and is satisfied that they are correct.

15. Further, the following guidelines are reiterated/guidance and for/compliance of all the concerned Officers involved in revision excercise:-

15.1 Display of list of claims and objections- (a) List of all claims and objections received should be put up on the website of CEO so that any citizen is able to see the list and lodge objections with the concerned ERO. In addition to this –

i. Adequate publicity should be given by CEO to the fact that list of claims and objections is available on his/her website and objections can be raised before the EROs based on this list.
ii. CEO, all DEOs and all EROs should hold meetings with political parties and inform them about the publication of list of claims and objections on CEO's website and the latest instructions of the Commission about disposal of claims and objections.
iii. Political parties should be informed in writing by the CEO/DEO/ERO about publication of list of claims and objections on CEO's website.

iv. List of claims and objections should be made available by ERO to all political parties on weekly basis. For this purpose, the ERO should call a meeting of all political parties on regular interval and personally handover list of claims and objections to them and obtain acknowledgment. It is to be added that the list should be incremental instead of cumulative.

15.2 Decisions on Claims and Objections - Decision on claims and objections should be taken only after all of the following conditions are compiled –

i. At least seven clear days' period has passed after list of claims and objections has been published on all of the following –
   (1) Website of CEO as clickable lists for each polling station
   (2) Notice board of ERO (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)
   (3) Notice board of polling station (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)
   (4) A personal notice has been served on the person whose name is proposed to be deleted in cases other than death cases.

ii. At least period of seven clear days has passed after furnishing the list of claims and objections to political parties.

iii. All deletions on the ground of death shall be made only after ascertaining the fact of death, to the satisfaction of ERO.

15.3 Verification before decisions on deletions –

i. All deletions except those done on the ground of death should be verified by an officer not below the rank of Tehsildar before final order is passed on Form 7.

ii. All cases of deletions must be cross verified personally by Electoral Registration Officer if they fall in any of the following categories: -

- Deletions in polling stations where the number of deletions exceed 2% of the total electors in the voters' list of the polling stations.
- Deletions where the same person is the objector in more than 5 cases.

iii. Cases of deletions other than those made on the ground of, should be cross verified by supervisory officers in the following manner:-
   (1) 2 % verification by Deputy DEO or equivalent officer.
   (2) 1 % verification by DEO.
   (3) 0.5 % verification by Roll Observer.

15.4 Monitoring - Monitoring report in the prescribed format as available at Electoral Roll Monitoring Application at CEO's portal shall be updated periodically by the CEO/DEO/ERO as the case may be. CEO shall compile the report and furnish the same to the Commission with his/her

comments. The DEO/CEO shall personally ensure that data entry is updated in All India E-Roll Monitoring Application in ECI portal through CEO's portal.

16. It is further clarified that all the Forms received during Special Drive 2017 shall be disposed of and registered death cases be removed from the roll after following due procedure. The supplements shall be prepared well before the draft publication of electoral rolls, 2018 so that outcome of disposal is reflected in integrated draft electoral roll at the time of its publication.

17. Preparation of Elector Photo Identity Card (EPIC) for the first time young electors may be done latest by **20th January 2018** and handed over to BLO/ERO/DEO etc. by **22nd January 2018** for ceremonial distribution on **25th January 2018**, the National Voters' Day.

18. The CEOs and all officers are further requested to extensively use the e-mail facility for prompt and accurate exchange of communication.

19. A copy of this letter should also be circulated among all DEOs/EROs in the State for taking immediate appropriate necessary action.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

ANNEXURE TO LETTER NO 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER2017 (VOL-II), DATED: 23RD AUGUST, 2017

Schedule for Special Summary Revision of Electoral Rolls w.r.t. 1st January, 2018 as qualifying date (Except Gujarat and Himachal Pradesh)

S. No.	Name of STATE/UT	Stages of Revision						
		Draft publiction of Electoral Rolls	Period for filing of claims and objections	Reading of relevant part/section of photo electoral rolls in Gram Sabha/Local Bodies and RWA meetings etc. and verification of names	Special Campaign dates with Booth Level Agents of political parties for receiving Claims and Objections	Disposal of Claims and Objections by	Updating the database, merging of photographs, updating the Control Tables and preparation and printing of supplementary list by	Final Publication of Electoral Rolls on
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ANDHRA PRADESH	1.11.2017	From 1.11.2017 to 25.11.2017	7.11.2017 and 14.11.2017	12.11.2017 and 19.11.2017	10.12.2017	25.12.2017	05.01.2018
2	ARUNACHAL PRADESH	3.10.2017	From 3.10.2017 to 23.10.2017	6.10.2017 and 13.10.2017	8.10.2017 and 15.10.2017	15.11.2017	20.12.2017	05.01.2018
3	ASSAM	16.10.2017	From 16.10.2017 to 15.11.2017	20.10.2017 and 3.11.2017	22.10.2017 and 5.11.2017	15.12.2017	22.12.2017	12.01.2018
4	BIHAR	4.10.2017	From 4.10.2017 to 31.10.2017	11.10.2017 and 18.10.2017	14.10.2017 and 21.10.2017	30.11.2017	26.12.2017	10.01.2018
5	CHHATTISGARH	23.10.2017	From 23.10.2017 to 22.11.2017	29.10.2017	5.11.2017	12.12.2017	30.12.2017	10.01.2018
6	GOA	18.09.2017	From 18.09.2017 to 17.10.2017	19.09.2017 and 31.10.2017	24.09.2017 and 8.10.2017	17.11.2017	16.12.2017	08.01.2018
7	HARYANA	3.10.2017	From 3.10.2017 to 2.11.2017	10.10.2017 and 17.10.2017	15.10.2017 and 29.10.2017	2.12.2017	27.12.2017	10.01.2018
8	JAMMU & KASHMIR	03.10.2017	03.10.2017 to 01.11.2017	04.10.2017 and 18.10.2017	14.10.2017 and 21.10.2017	30.11.2017	15.12.2017	01.01.2018
9	JHARKHAND	16.10.2017	From 16.10.2017 to 15.11.2017	23.10.2017 and 7.11.2017	29.10.2017 and 5.11.2017	11.12.2017	From 11.12.2017 to 29.12.2017	08.01.2018
10	KARNATAKA	25.10.2017	From 25.10.2017 to 24.11.2017	03.11.2017 and 15.09.2017	05.11.2017 and 19.11.2017	20.12.2017	11.01.2018	12.01.2018
11	KERALA	31.10.2017	From 31.10.2017 to 30.11.2017	04.11.2017 and 18.09.2017	11.11.2017 and 26.11.2017	20.12.2017	30.12.2017	15.01.2018
12	MADHYA PRADESH	4.10.2017	From 4.10.2017 to 3.11.2017	11.10.2017 and 18.10.2017	8.10.2017 and 29.10.2017	30.11.2017	20.12.2017	10.01.2018
13	MAHARASHTRA	3.10.2017	From 3.10.2017 to 3.11.2017	7.10.2017 and 13.10.2017	8.10.2017 and 22.10.2017	5.12.2017	20.12.2017	05.01.2018
14	MANIPUR	4.10.2017	From 4.10.2017 to 3.11.2017	7.10.2017 and 20.10.2017	8.10.2017 and 22.10.2017	24.11.2017	8.12.2017	05.01.2018
15	MEGHALAYA	27.09.2017	From 27.09.2017 to 31.10.2017	6.10.2017 and 18.10.2017	7.10.2017 and 21.10.2017	13.11.2017	19.12.2017	10.01.2018
16	MIZORAM	15.09.2017	From 15.09.2017 to 13.10.2017	16.09.2017 and 30.09.2017	23.09.2017 and 07.10.2017	10.11.2017	20.12.2017	15.01.2018
17	NAGALAND	3.10.2017	From 3.10.2017 to 31.10.2017	13.10.2017 and 27.10.2017	14.10.2017 and 28.10.2017	30.11.2017	20.12.2017	05.01.2018
18	ODISHA	18.09.2017	From 18.09.2017 to 31.10.2017	20.09.2017 and 29.10.2017	8.10.2017, 15.10.2017 and 22.10.2017	30.11.2017	28.12.2017	15.01.2018
19	PUNJAB	3.10.2017	From 3.10.2017 to 02.11.2017	07.10.2017 and 14.10.2017	08.10.2017 and 15.10.2017	01.12.2017	From 05.12.2017 to 20.12.2017	08.01.2018
20	RAJASTHAN	30.10.2017	From 30.10.2017 to 20.11.2017	11.11.2017 and 18.11.2017	12.11.2017 and 19.11.2017	04.12.2017	From 05.12.2017 to 29.12.2017	05.01.2018
21	SIKKIM	18.09.2017	From 18.09.2017 to 17.10.2017	20.09.2017 and 06.10.2017	24.09.2017 and 08.10.2017	18.11.2017	15.12.2017	05.01.2018
22	TAMIL NADU	3.10.2017	From 3.10.2017 to 31.10.2017	7.10.2017 and 21.10.2017	08.10.2017 and 22.10.2017	10.12.2017	From 11.12.2017 to 03.01.2018	05.01.2018
23	TELANGANA	1.11.2017	From 1.11.2017 to 25.11.2017	7.11.2017 and 14.11.2017	12.11.2017 and 19.11.2017	10.12.2017	25.12.2017	05.01.2018
24	TRIPURA	24.08.2017	From 24.08.2017 to 22.09.2017	09.09.2017 and 16.09.2017	27.08.2017, 03.09.2017 and 17.09.2017	31.10.2017	30.11.2017	05.01.2018
25	UTTARAKHAND	10.10.2017	From 10.10.2017 to 10.11.2017	17.10.2017 and 24.10.2017	22.10.2017 and 4.11.2017	30.11.2017	10.01.2018	15.01.2018
26	UTTAR PRADESH	15.09.2017	From 15.09.2017 to 30.10.2017	16.09.2017, 03.10.2017 and 24.10.2017	17.09.2017, 08.10.2017 and 29.10.2017	4.12.2017	From 04.12.2017 to 26.12.2017	02.01.2018
27	WEST BENGAL	22.08.2017	From 22.08.2017 to 13.09.2017	26.08.2017 and 09.09.2017	27.08.2017 and 10.09.2017	15.11.2017	15.12.2017	05.01.2018

S. No.	Name of STATE/UT	Stages of Revision						
		Draft publiction of Electoral Rolls	Period for filing of claims and objections	Reading of relevant part/section of photo electoral rolls in Gram Sabha/Local Bodies and RWA meetings etc. and verification of names	Special Campaign dates with Booth Level Agents of political parties for receiving Claims and Objections	Disposal of Claims and Objections by	Updating the database, merging of photographs, updating the Control Tables and preparation and printing of supplementary list by	Final Publication of Electoral Rolls on
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	A & N ISLANDS	31.10.2017	From 31.10.2017 to 30.11.2017	04.11.2017 and 18.11.2017	11.11.2017 and 25.11.2017	15.12.2017	30.12.2017	13.01.2018
29	CHANDIGARH	3.10.2017	From 3.10.2017 to 31.10.2017	06.10.2017 and 13.10.2017	08.10.2017 and 22.10.2017	30.11.2017	22.12.2017	10.01.2018
30	DAMAN & DIU	18.09.2017	From 18.09.2017 to 17.10.2017	22.09.2017 and 06.10.2017	22.09.2017 and 07.10.2017	17.11.2017	15.12.2017	05.01.2018
31	D & N HAVELI	15.09.2017	From 15.09.2017 to 13.10.2017	16.09.2017 and 07.10.2017	17.09.2017 and 08.10.2017	1.12.2017	1.1.2018	05.01.2018
32	NCT OF DELHI	23.10.2017	From 23.10.2017 to 13.11.2017	28.10.2017 and 04.11.2017	29.10.2017 and 5.11.2017	11.12.2017	26.12.2017	08.01.2018
33	LAKSHADWEEP	15.09.2017	From 15.09.2017 to 16.10.2017	18.09.2017 and 03.10.2017	24.09.2017 and 15.10.2017	20.11.2017	20.12.2017	10.01.2018
34	PUDUCHERRY	15.09.2017	From 15.09.2017 to 14.10.2017	16.09.2017 and 10.10.2017	24.09.2017 and 08.10.2017	16.11.2017	15.12.2017	05.01.2018